

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक-24 जुलाई, 2020

विषय:-15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि रु0. 2438 करोड़ टाईड ग्रांट के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-15(2)एफ0सी0-एक्स0वी0/एफ0सी0डी0/2020-21, दिनांक-01.06.2020 तथा पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी0-39011/2/2017 एफ0डी0, दिनांक-02.07.2020 से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को दो भागों में-50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अनटाईड ग्रांट (बेसिक अनुदान) के रूप में तथा 50 प्रतिशत धनराशि टाईड ग्रांट के रूप में अनुमन्य की गयी है। वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित धनराशि का व्यय, उपभोग सुनिश्चित किया जायेगा:-

1- पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला:-

1.1- ग्रामीण निकायों के मध्य धनराशि का वितरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1594/33-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 में निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा। इस प्रकार जनपद को उपलब्ध संक्रमित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि का 15 प्रतिशत अंश से सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत को 15 प्रतिशत अंश क्षेत्र पंचायतों को एवं 70 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित किया जाएगा।

2- 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनटाइड/बेसिक ग्राण्ट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपभोग हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार के पत्र सं0-F.No. G-39011/2/2017-FD दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत किए गए हैं, जो निम्नवत हैं:

"Storm Water Drainage and water logging management, immunization of children, prevention of malnutrition of children, construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat (GP) and inter GP, construction and repair of foot paths within GP and inter GP, construction and repair and maintenance of LED street lights and solar lighting as applicable (solar street light may be individual poles or centralized solar panel system)- within GP and inter GP, construction, repair and maintenance of crematorium and acquisition of land for crematorium and cremation grounds, acquisition of land & maintenance and upkeep of dead body burial ground, providing sufficient and high bandwidth Wi-Fi digital network services within GP, public library; recreation facilities including children's park; playground; rural haat; sports & physical fitness equipment, etc. and any other basis improved/enhanced service mandated by state government under relevant state legislation; (recurring expenditure for electricity, water, collection and disposal & recycling waste, liquid/solid waste management equipment, manpower on outsourcing basis and other administrative expenses as essential, immediate relief works in the event of natural disasters/pandemic; discharge of responsibilities specifically mandated to panchayat under various Acts/Laws e.g preparation and updation of people' s biodiversity register (PBR) under biodiversity Act, 2002"

The XV FChas not distinguished between O&M and capital expenditure within the component of locally felt needs. GPs can enter into annual maintenance contracts/service contracts for providing the services to rural inhabitants. However, expenditure from the grants on

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

the negative list namely expenditure on items already being funded from other schemes, felicitation/cultural functions/ decorations/ inauguration, Honorarium, TA/DA of elected representatives and salaries/honorarium of existing employees/permanent, doles/awards entertainment, purchase of vehicles and air-conditioners are not allowed under this component."

3-15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाईड ग्रांट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपभोग हेतु निर्देश

भारत सरकार द्वारा इस विषय पर निर्गत Operational Guideline दिनांक 01.06.2020 निम्नवत हैं :

"Tied Grants:- Tied grants i.e. 50% of the allocation will be released in two instalments by the Ministry of Finance, Department of Expenditure (Finance Commission Division) after receipt of recommendation from the Ministry of Panchayati Raj, Govt. of India. Department of Drinking Water & Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Govt. of India and MOPR will assess the following before recommending for release of grant;

- (a) Status & maintenance of Open Defecation Free local body
- (b) Supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling.
- (c) Uploading of GPDP and details about utilization 15th F.C. funds on the website.
- (d) Any other condition which Ministry of Jal Shakti may deem fit in connection with the stated objectives of the tied grant.

Tied Grants:- The tied grants can be used for the basic services of (a) sanitation and maintenance of open-defecation free (ODF) status and (b) supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling. The local bodies shall, as far as possible earmark one half of these tied grants each to these two critical services. However, if any local body has fully saturated the needs of one category, it can utilise the funds for the other category.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3.1 टाईड ग्रान्ट में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण :

- (a) सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख-रखाव की व्यवस्था।
- (b) Grey Water (किचेन व बाथरूम) का Treatment एवं Management
- (c) सीवर प्रणाली (Shallow Bore/Deep Bore) का विकास तथा रख-रखाव
- (d) सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था- Waste stabilization Pond आदि
- (e) सेप्टेज ट्रीटमेंट व मैनेजमेंट
- (f) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का निर्माण व रख-रखाव आदि
- (g) पाईप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना इसका रख-रखाव
- (h) वर्षा जल का संचयन
- (i) ट्रीटेड जल का recycle एवं reuse
- (j) पाईपड पेयजल की योजनाएं ग्राम पंचायतों की सहमति से क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत द्वारा बनाई व संचालित की जा सकती है।
- (k) प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट- प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक व थर्मोकोल के विनिर्माण व प्रयोग को रोकने की व्यवस्था। अधिसूचना सं0-2893/33-3-2019-154-2014, टी0सी0 दिनांक 10 जनवरी, 2020 के अनुसार प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना तथा संग्रहण reuse व recycle की व्यवस्था बनाना।

4- अनटाईड/बेसिक ग्रान्ट का इस्तेमाल सर्वप्रथम पंचायत घर के निर्माण पर किया जाएगा। टाईड ग्रान्ट के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही धनराशि से सैनीटेशन मद के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत धनराशि से सर्वप्रथम सामुदायिक शौचालय के निर्माण व रख-रखाव की व्यवस्था की जाएगी।

5- अनटाईड ग्रान्ट तथा टाईड ग्रान्ट का उपभोग उपरोक्त कार्यों हेतु ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें कर सकेंगी।

जिला पंचायतें व क्षेत्र पंचायतें सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख-रखाव कस्बे/बाजार/हॉट व ऐसे स्थल जहाँ लोगों का आवागमन अधिक है, वहाँ करेंगी।

जिला पंचायतें एवं क्षेत्र पंचायतें प्रदेश के नेशनल हाईवे/स्टेट हाईवे/मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आदि जिन पर आवागमन अधिक रहता है, वहाँ उचित स्थलों पर Rest Area/जन-सुविधा केन्द्र (शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों के पार्किंग) के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं।

जिला/क्षेत्र पंचायतें अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बाजारों, हॉट पैठें, पशु बाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व भुगतान

के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:-

समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के इण्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (E-Gram Swaraj_) के माध्यम से की जायेगी।

6.1 यह धनराशि 15वें वित्त आयोग के लिए खोले गए बैंक खाते में ही ब्यवहरित की जाएगी।

6.2 सर्वप्रथम समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15वें वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर ई-ग्राम स्वराज साफ्टवेयर पर अपनी वार्षिक ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करेंगी।

6.3 उक्तानुसार प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई-ग्राम स्वराज के साफ्टवेयर पर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग मद में अंकित की जायेगी।

6.4 तत्पश्चात् प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) के सापेक्ष समस्त भुगतान ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो कि पी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर से एकीकृत है) के माध्यम से किया जायेगा।

6.5 प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान (यथा-वेन्डर एवं श्रमिकों का भुगतान) सीधे उनके बैंक खातों में ई-ग्राम स्वराज-पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त टाईड ग्रांट की धनराशि रू0. 2438 करोड़ का फॉट जनपदों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों का विवरण संलग्नक पर है।

7- वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाईनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित-1/2017, दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जाएगा।
- 9- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-14 के लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग-0301 सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या-20-सहायता (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।
- 10- उपरोक्तानुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त टाईड ग्रांट की कुल धनराशि ₹0. 243800.00 लाख को निम्नानुसार संलग्न फॉट के अनुसार उपरोक्त शतोर एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	पंचायती राज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि ₹0. में
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	17,06,60,00,000/-
योग		24,38,00,00,000/-

- 11- यह आदेश भारत सरकार के पत्र संख्या-F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 15.07.2020 एवं वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं के0स0) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0161/ दस-2020-2/2020 के क्रम में निदेशक, पंचायती राज द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव संबंधी पत्र संख्या-8/3863/2019-8/98/2019-20 दिनांक 23 जुलाई 2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1/149/दस-2020-231 /2019, दिनांक 24.03.2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

उक्त के क्रम में से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जनपदों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का व्यय उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के मध्य टाइड ग्रान्ट की प्रथम किस्त की धनराशि रु. 243800.00 लाख अवमुक्त किए जाने हेतु जनपदवार फाण्ट

(धनराशि रु. में)

क्र.सं.	जनपद	ग्राम पंचायत	क्षेत्र पंचायत	जिला पंचायत	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	182931377	39199581	39199581	261330539
2	बागपत	112215305	24046137	24046137	160307579
3	गाजियाबाद	76034097	16293021	16293021	108620139
4	गौतमबुद्धनगर	36841839	7894680	7894680	52631199
5	बुलन्दशहर	295021173	63218823	63218823	421458819
6	सहारनपुर	265870284	56972204	56972204	379814692
7	मुजफ्फरनगर	238627820	51134533	51134533	340896886
8	आगरा	282380857	60510184	60510184	403401225
9	अलीगढ़	263678288	56502490	56502490	376683268
10	हाथरस	132612486	28416961	28416961	189446408
11	एटा	170573764	36551521	36551521	243676806
12	कासगंज	130075536	27873329	27873329	185822194
13	मैनपुरी	173631997	37206857	37206857	248045711
14	मथुरा	188461131	40384528	40384528	269230187
15	फिरोजाबाद	182169597	39036342	39036342	260242281
16	बरेली	329521963	70611849	70611849	470745661

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

17	बदायू	283224360	60690934	60690934	404606228
18	पीलीभीत	195403597	41872199	41872199	279147995
19	शाहजहापुर	267340483	57287246	57287246	381914975
20	मुरादाबाद	210761249	45163125	45163125	301087499
21	अमरोहा	154641283	33137418	33137418	220916119
22	रामपुर	188884229	40475192	40475192	269834613
23	बिजनौर	314452739	67382730	67382730	449218199
24	लखनऊ	141525050	30326796	30326796	202178642
25	रायबरेली	285719776	61225666	61225666	408171108
26	अमेठी	202837980	43465281	43465281	289768542
27	हरदोई	408040368	87437222	87437222	582914812
28	उन्नाव	294300150	63064318	63064318	420428786
29	सीतापुर	441138806	94529744	94529744	630198294
30	खीरी	409143461	87673599	87673599	584490659
31	अयोध्या	225041953	48223276	48223276	321488505
32	अम्बेडकर नगर	228388770	48940451	48940451	326269672
33	सुल्तानपुर	248444574	53238123	53238123	354920820
34	बाराबंकी	319321332	68426000	68426000	456173332
35	गोण्डा	358358264	76791057	76791057	511940378
36	बलरामपुर	222669345	47714860	47714860	318099065
37	बहराइच	353759796	75805671	75805671	505371138
38	श्रावस्ती	119700861	25650185	25650185	171001231
39	प्रयागराज	462059721	99012797	99012797	660085315

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

40	कौशाम्बी	146302661	31350570	31350570	209003801
41	फतेहपुर	260393231	55798550	55798550	371990331
42	प्रतापगढ़	318312315	68209782	68209782	454731879
43	वाराणसी	216088057	46304584	46304584	308697225
44	चन्दौली	191185111	40968238	40968238	273121587
45	गाजीपुर	361731401	77513872	77513872	516759145
46	जौनपुर	436147335	93460143	93460143	623067621
47	मिर्जापुर	250798908	53742623	53742623	358284154
48	सोनभद्र	210234523	45050255	45050255	300335033
49	संतरविदास नगर (भदोही)	144278017	30916718	30916718	206111453
50	हमीरपुर	116324981	24926782	24926782	166178545
51	बांदा	183378797	39295457	39295457	261969711
52	चित्रकूट	112927235	24198693	24198693	161324621
53	महोबा	94502344	20250502	20250502	135003348
54	गोरखपुर	369655764	79211949	79211949	528079662
55	महाराजगं ज	261397388	56013726	56013726	373424840
56	देवरिया	296723253	63583554	63583554	423890361
57	कुशीनगर	325782809	69810602	69810602	465404013
58	बस्ती	245451015	52596646	52596646	350644307
59	सन्त कबीर नगर	163084101	34946593	34946593	232977287

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

60	सिद्धार्थ नगर	245842421	52680519	52680519	351203459
61	आजमगढ़	456108839	97737608	97737608	651584055
62	मऊ	175841538	37680330	37680330	251202198
63	बलिया	312338490	66929676	66929676	446197842
64	कानपुर नगर	178887168	38332965	38332965	255553098
65	कानपुर देहात	180925725	38769798	38769798	258465321
66	फर्रुखाबाद	162422206	34804758	34804758	232031722
67	कन्नौज	153778753	32952590	32952590	219683933
68	इटावा	139286092	29847020	29847020	198980132
69	औरैया	130786376	28025652	28025652	186837680
70	झांसी	155527571	33327337	33327337	222182245
71	ललितपुर	141914930	30410342	30410342	202735614
72	जालौन	133762405	28663373	28663373	191089151
73	शामली	102866370	22042794	22042794	146951958
74	सम्भल	192756038	41304861	41304861	275365760
75	हापुड़	102450171	21953608	21953608	146357387
	योग-	17066000000	3657000000	3657000000	24380000000

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।